

estimated that unemployment will be reduced to around 10 million by the end of the plan and to about 3 million by 2000 A.D.

जिलास्तरीय विकास योजना तैयार किया जाना

@@2641. श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आगामी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिलास्तरीय विकास योजना तैयार करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारस्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) आठवीं योजना में जिला योजना के महत्व पर जोर दिया जाता रहेगा। योजना आयोग 1969 से जिला योजनाएं तैयार करने के लिए कहता रहा है। राज्यों को जिला योजनाएं तैयार करने में समर्थ बनाने के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर योजना मशीनरी को सुदृढ़ बनाने की योजना के तहत राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ताकि उन्हें मॉडल योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। योजना आयोग के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा तैयार किए गए पांच जिलों के लिए मॉडल योजनाएं तथा जिला योजनाओं के लिए दिशा निर्देश भी हैं। जिला योजनाएं बनाने के लिए ये दिशा निर्देश राज्यों को परिचालित कर दिए गए हैं। राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे जिला स्तर स्तरीय योजनाएं बनाने

@@ पूर्वतः अतिरिक्त प्रश्न 1737, 24 जुलाई 1992 से स्थानान्तरित।

के लिए जिला योजना मशीनरी को अधिक स्वतंत्रता दे। महसूस की गई आवश्यकताओं पर आधारित योजनाएं आरम्भ करने के लिए "मुक्त" विधियों के प्रावधान को प्रोत्साहित किया जाता है :

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य

@@@2642. श्री विनोद शर्मा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में औद्योगिक उत्पादन की विकास-दर के लिए रखा गया लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना में रखे गये लक्ष्य की तुलना में कम है ;

(ख) यदि हाँ, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन की विकास-दर का क्या लक्ष्य रखा गया था और आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य कितना होगा ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्पादन की विकास-दर का लक्ष्य कम रखे जाने के क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारस्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्षेत्रीय विकास दरों का पूर्व अनुमान पिछले कार्य निष्पादन विकास के लिए संभावनाएं तथा योजना की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस प्रकार आठवीं योजना में 5.6 प्रतिशत की लक्ष्य की गई सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों की अपेक्षित वृद्धि निम्न प्रकार है :

@@@ पूर्वतः अतिरिक्त प्रश्न 1553, 23 जुलाई, 1992 से स्थानान्तरित।

सकल नूतन संवर्धित की लक्ष्य वृद्धि दर

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

	सातवीं योजना	आठवीं योजना
खनन तथा उत्खनन	11.7	8.1
विनिर्माण	5.5	7.5
बिजली गैस तथा जल आपूर्ति	7.9	8.2
सकल घरेलू उत्पाद	5.0	5.6

Setting up of Small Farmers Agri-cultural Business Consortium

\$2643. SHRI SHANTI TYAGI:
MISS SAROJ KHAPARDE:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up small farmers' agri-business consortium;

(b) if so, what are the details thereof and what will be its functions; and

(c) by when the consortium is likely to start function?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) Yes, Sir. As announced in the Budget 1992-93, a Small Farmers' Agri-Business Consortium with funding from Reserve Bank of India, Industrial Development Bank of India and National Bank for Agriculture &

Rural Development is to be set up. The consortium would be an autonomous corporate entity and will have representation from the IDBI, NABARD and other financial institutions, public sector corporation dealing with agriculture and agro- industries as well as private sector companies. The scheme envisages giving employment and income generation orientation to the crop husbandry, animal husbandry, agro forestry, fisheries, agro processing and agro based industries sectors during the Eighth Plan period and beyond creating more skilled jobs in the country in the short term by using the underutilised opportunities in the farm sector, developing organisational structures which can promote group cooperation both at the production and marketing phase and establish links in the production processing and marketing chain for making programmes economically viable and replicable.

(c) The consortium is scheduled to function in the current year i.e. 1992-93.

SPreviously Unstarred question 1656, transferred from the 24th July, 1992:.